[श्री कंवर लाल गुप्त]

डिस्कशन जल्दी खत्म होने वाला नहीं है इसलिये इसको कल लिया जाय और मेरे विषय पर बहस शुरू की जाय ।

सभापति महोदय : जिन्होंने अमेण्डमेन्ट्स दी हैं, उनके बाद ।

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : May I submit that we have our other engagements and we have adjusted our programme according to this ? Therefore we would like you to take up the next item.

MR. CHAIRMAN : That will take only five minutes.

SHRI BAL RAJ MADHOK : You are not going to finish it in five minutes.

MR. CHAIRMAN : I will call only Shri Dandeker and than take up the next item.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Then the Minister will reply. In this already five minutes have gone.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : This is an important clause. Of course, Shri Madhu Limaye has said that those who have not moved amendments should not be allowed to speak but this is a matter on which some of our Members also would like to offer their opinion. I therefore request you to consider this matter and allow some more time.

MR. CHAIRMAN : Others will be given time but after we have finished with the list of those who have move amendments.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : How can they speak in support just in five minutes ?

MR. CHAIRMAN : Not today.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Then, hold it over.

MR. CHAIRMAN : All right.

17.03 hrs.

DISCUSSION RE : DETERIORATING LAW AND ORDER SITUATION IN DELHI

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति जी, दिल्ली में अपराधों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि हम रोजाना समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि आज वहां पर कत्ल हो गया, कल वहां कत्ल हो गया । कत्ल, छुरेबाजी, चोरी और डकैती की वारदातें रोजाना बढ़ती जा रही हैं । सभापति जी, आप स्वयं दिल्ली में रहते हैं, जितनी इनसिक्योरिटी आज एक कौमन-मैन दिल्ली में फील करता है, वैसी कभी नहीं थी । ये सोफेस्टीकेटेड क्राइम्ज आर्गनाइज्ड गैंग्ज के जरिये होते हैं और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना कुछ होने के बाद भी आज तक पुलिस को जो कार्यवाही करनी चाहिये, उसमें पुलिस पूरी तरह से कोताही कर रही है ।

सभापति जी, आपने पढ़ा होगा—कोई भी कत्ल होता है, पुलिस उसका कुछ न कुछ जवाब दे देती है । मुझे मालूम है कि मंत्री जी कुछ आंकड़े देंगे, जो उनका हमेशा का टैकनीक है, कि पहले इतने कत्ल हुए, इस साल इतने कत्ल हुए, पहले इतनी चोरियां हुईं, इस साल इतनी हुई । मुझे इन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है । ये आंकड़े लोगों को तसल्ली नहीं दे सकते, ये आंकड़े लोगों के मन में सिक्योरिटी नहीं ला सकते, विश्वास नहीं ला सकते । जब तक पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठायगी, तब तक लोगों के अन्दर विश्वास नहीं आ सकता कि पुलिस उनकी रक्षा कर सकती है ।

यह सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है । गाजियाबाद यू० पी०, हरियाणा, पंजाब, आसपास के जो गुण्डे हैं यहां आकर ठहरते हैं और दिल्ली एक ऐसा केन्द्र बन गया है जहां पर हम कह सकते हैं कि यह सेफेस्ट-हाइड-आउट हो गया है, जहां वे सुरक्षा से और आराम से रहते हैं । यहां की पोश-कालोनीज के अन्दर, डिफेन्स कालोनी और दूसरी कालोनीज में सोफेस्टिकैटेड क्राइम्ज होते हैं । वहां नेकेड-फिल्म्ज दिखाई जाती हैं, जिसके लिये एन्ट्री का 20-20 और 25-25 रुपया लिया जाता है, वहां लिकर सर्व होती है, और सब

तरह की खुराफात वहां होती है ...

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कहां होती हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : कहीं भी जाकर देख लीजिये ।

एक आतंक दिल्ली के लोगों में छा गया है । लोगों की पुलिस में विश्वास नहीं रहा है और जब हम यहां बहस उठाते हैं तो मंत्री महोदय उसका जवाब दे देते हैं—कह देते हैं कि इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे । लेकिन हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक कोइ ठोस कदम नहीं उठाया जायेगा, काम नहीं चलेगा । ये आंकड़े तो धोखा देने वाले हैं ।

मेरी अपनी कांस्टीचूएन्सी में पिछले सप्ताह एक ही दिन में तीन कत्ल हुए । मल्का गंज, सब्जी मंडी में दो बच्चों का कत्ल हुआ । एक की उम्र 6 साल थी और दूसरे की तीन साल थी : वहां के स्कूल के चौकीदार का कत्ल किया गया - तीनों कत्ल एक ही समय में हुए—शाम के 6 बजे के लगभग और पुलिस ने उसकी एक शानदार कहानी बना दी कि ये तीनों कत्ल सोडेमी की वजह से हुए । एक मनगढ़न्त कहानी उन्होंने बनाकर पेश कर दी उन्होंने कहा है कि उसने बच्चों के साथ नाजा-यज़-फेल किया और जब बच्चा बेहोश हो गया तो छोटा बच्चा वहां खेल रहा, उसको कत्ल कर दिया, उसके बाद बड़े को कत्ल किया, उस के बाद खुद फांसी लगाकर मरने की कोशिश की, जब फाँसी नहीं लगी तो छुरी से रस्सी कांट दी और फिर कौपर-सल्फेट खा लिया । इस तरह से पुलिस ने एक अजीब सी कहानी बनाकर तीनों कत्ल कैसे हुए एक्सप्लेन कर दिया ।

मेरा कहना है कि अगर मंत्री महोदय उस इलाके में जा कर देखें तो उनको मालूम होगा कि एक दिन पहले उस व्यक्ति ने जिसके बच्चे कत्ल हुए हैं, पुलिस के पास जा कर यह कहा था कि स्कूल के अन्दर गुण्डे आकर रोज शराब पीते हैं, बदमाशी होती है, इसको रोकना चाहिए । लेकिन थाने वालों ने उसकी रिपोर्ट को नहीं लिखा । सभापति जी, जब उसके दो बच्चे चले गये और वह यह कहानी सुनता है, जो पुलिस ने बनाई है, तो यह बात जखम पर नमक छिड़कने जैसी है । इस तरह की कहानी पुलिस बना सकती है, लेकिन इससे लोगों के अन्दर विश्वास आने वाला नहीं है । आज दिल्ली की पुलिस की यह हालत हो गई है कि जिस तरह से शमशान में एक पुजारी होता है, एक मुर्दा आता है, वह मंत्र पढ़ता है, सवा रुपया लेकर कह देता है कि आग लगाओ, फिर दूसरा मुर्दा आता है, उसके साथ भी वही व्यवहार करता है । फिर तीसरा आता है, उसके साथ भी वह वही व्यवहार करता है । उसके चेहरे से कोई दुख प्रकट नहीं होता है, चाहे किसी का जवान मरा हो या छोटा मरा हो, वह तो अपना काम रोटीन की तरह से करता जाता है । उसी तरह से आज दिल्ली की पुलिस पर कोई असर नहीं होता है । वे कहते हैं कि अखबार वाले तो वैसे ही शोर मचाते हैं, हाईलाइट करते हैं । जब तक मंत्री महोदय इसके बारे में नहीं सोचेंगे जब तक कोई काम चलने वाला नहीं है । पुलिस एक रास्ता और निकालती है । जो रोज कत्ल होते हैं और शोर मचता है तो उसपर कहा जाता है कि राजनीतिक दल गड़बड़ करते हैं । राजनीतिक नेता कुछ गुंडों को पालते हैं—यहाँ तक कि ले० गवर्नर ने भी यह बात कही और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा लेकिन अखबार वालों ने कंट्राडिक्ट किया कि उन्होंने कहा है । तो मैं कहना चाहता हूँ यह उनका कवर है । दिल्ली में कोई किसी पार्टी का हो, हो सकता है इस तरह के दो केसेज हों लेकिन इस तरह कि इन्टरफियरेन्स या इस तरह की चीज नहीं होती है । केवल अपनी कमी और क्राइम्स को छिपाने के लिए इस तरह की आड़ ली जाती है और लोगों को बदनाम किया जाता है । अगर कोई ऐसा पोलिटिकल लीडर है तो उसका

[श्री कंवर लाल गुप्त]

कहना पुलिस को क्यों मानना चाहिए ? उनके पास तो कानून है, ताकत है उन्हें उसको सजा देनी चाहिए। जब हमारी मीटिंग हुई ले० गवर्नर के यहाँ तो सभी पार्टी के लोगों ने कहा कि अगर ऐसा कोई हो तो पब्लिकली आप उन पार्टी के लीडर्स को बतलाइए ताकि हर एक समझ जाये कि हमारा व्यक्ति गलत काम करता है, उसको यह काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि यह केवल एक कवर है, आड़ है, अपने पापों पर पर्दा डालने के अलावा और कुछ भी नहीं है।

सभापति जी, इसके क्या कारण हैं ? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत करप्शन है। करप्शन का सबसे बड़ा कारण जैसा कि हाई-कोर्ट के एक जज, जो कि इस सदन के सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा आर्गेनाइज्ड गैंग पुलिस है। मैं तो यह नहीं कहूंगा लेकिन यह जरूर कहूँगा कि उस आर्गेनाइज्ड गैंग के साथ दिल्ली पुलिस की एक्टिव कनाइवेन्स जरूर है। कोई थाना ऐसा नहीं है, कोई एस० एच० ओ० ऐसा नहीं है जो कि उन गुण्डों के साथ न मिला हो। एक थाने की 50 हजार रुपए से लेकर पाँच लाख रुपए तक की पर मंथ आमदनी है। रिश्वत का बाजार गरम है। आप कहेंगे कि मैं स्वीपिंग रिमार्क्स कर रहा हूँ। मेरे पास खोसला कमीशन की रिपोर्ट है। मैं उसमें से कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि करप्शन के बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के पेज 489 पर लिखा है :—

> "We, therefore, see that almost every one agrees that corruption is prevalent to a very large extent in the police force among the low ranks and in a smallar measure in the higher echelons. It is not possible to say whether the constabulary is corrupt to the extent of 80 per cent or 90 per cent, but there is little doubt that, judging by the volume of complaints, it may be assumad that there is hardly a police constable or head constable or who can be said to be free from the canker of corruption; in any case, no: one of them is free from the chain of public accusation and mistrust. This is a very serious state of affairs and must be rectified at all costs."

यह उस कमीशन की रिपोर्ट करप्शन के बारे में है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट सर्वेन्टस के असेट्स के बारे में जांच कराते हैं लेकिन क्या कभी आपने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के असेट्स के बारे में भी जाँच कराई है। मैं कहता हूं आप जांच करायें। यह ठीक है कि पूरी तफसील सामने नहीं आयेगी लेकिन कुछ चीजें जरूर सामने आयेंगी। हो सकता है उससे सरकार को कुछ लाभ हो।

तीसरा कारण यह है कि पुलिस की जो संख्या है वह बहुत कम है। यहां पर ला एण्ड आर्डर की यह प्राब्लम है और दूसरी तरफ तमाम डिग्निटरीज आते रहते हैं और सारी पुलिस उसमें लगी रहती है। इन्वेस्टिगेशन और डेटेक्शन के काम की तरफ पुलिस का ध्यान ही नहीं जाता है। आज निक्सन साहब आये, कल कोई दूसरा और परसों कोई तीसरा आयेगा — सारी पुलिस उस तरफ चली जायेगी और जो कत्ल के मामले की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जायेगा। इसी कमीशन ने यह बात भी कही है कि दिल्ली में तीन डी० एस० पी० की कमी है, पाँच इंस्पेक्टर की कमी है, 202 सब इंस्पेक्टरों की कमी है, 405 हेड कांस्टेबिल्स की कमी है और 1186 कांस्टेबिल्स की कमी है। मुझे मालूम है कि आज मंत्री जी जो स्ट्रेन्थ सैंक्शन की है वह साल दो साल के बाद ही आ पायेगी। इसलिए मेरी मांग है कि अगर आप दिल्ली की पुलिस को माडल पुलिस बनाना चाहते हैं तो जब तक वे लोग ट्रेन हो कर आजायं तब तक के लिए आप आस पास की राज्य सरकारों से कहिए कि इस समय यहां पर जितनी कमी है उसको वे पूरा करें।

चौथी चीज यह है कि यहाँ के जो सीनियर

आफिसर्स हैं वे फील्ड में काम नहीं करते, उनका सुपर्विजन ठीक नहीं है—वे ज्यादातर किताबों और फाइलों का ही काम करते हैं। इसी कमीशन की रिपोर्ट से, किस तरह से काम होता है उसके बारे में भी पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पेज 151 पर उन्होंने कहा है :

> "The Commission during its inquiries found that in Delhi the Superintendent hardly ever supervises at the spot the investigation of a crime except in very sensational cases. The Sub Divisional Police Office supervises a few burglary and theft cases. The Superintendents spot report files are maintained by constables and Head Constables who make remarks for the Deputy Superintendent of Police to peruse. It is astonishing that this type of unauthorised and unwanted application should be a regular feature of Police work.

ये कितने डैमेजिंग रिमार्क्स हैं। समय थोड़ा है इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता, मेरा कहना यह है कि ये जो पुलिस स्टेशन हैं जबतक वे इफेक्टिव नहीं होंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। आज उनकी इमेज भी बड़ी खराब है। हर थाने वाले गुंडों के साथ मिले हुए हैं। हो सकता है कुछ आफीसर हों लेकिन कुछ न कुछ आफीसर जरूर उनके साथ मिले हुए हैं, उन्हीं की कनाइवेन्स से होता है। उनके बारे में जो इम्प्रेशन है वह भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ :

> Indeed almost all the public witnesses who appeared before the commission have testified that the Police have no public image at all. people do not trust them because they are unreliable and corrupt.

सभापति जी, आखीर में मैं कुछ सुझाव देकर समाप्त करना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहले कहना यह है कि मन्त्री महोदय अभी डी० एस० पी० और गजटेड आफिसर्स को दूसरे एरियाज में ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन अगर नीचे के आफिसर्स, एस० एच० ओ० वगैरह को भी ट्रांसफर करने की पावर लें, उनको भी दूर भेज सकें तो उससे सुविधा होगी। दूसरे, सेन्टर में जो सी० बी० आई० का मुहकमा है उसको कुछ दिनों के लिए सुपर्विजन करने के लिए लगाइए ताकि वे देखें कि ठीक तरह से रिपोर्ट दर्ज होती है या नहीं, रिश्वत कितनी है और जो रिश्वत लेते हैं उनको पकड़ करके आमने-सामने रख सकें। तीसरी चीज यह है कि आपने खोसला कमीशन की रिपोर्ट पर थोड़ा सा अमल किया है लेकिन ज्यादा चीजों पर अमल नहीं किया है। जबतक आप उनपर भी अमल नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चौथी चीज यह है कि जो डेटेक्शन और इवेस्टिगेशन का स्टाफ है, उसको आप अलग कीजिए। ला ऐन्ड आर्डर और डिग्निटरीज को मेनटेन करने के लिए आप अलग करिए। इसके अलावा आप एक पुलिस कमिशनर का एपवाइन्टमेंट कीजिए। यहां पर कोई यूनिफाइड स्थारिटी नहीं है। कहीं पर डी० एस०, कहीं पर आई० जी० और कहीं पर कोई दूसरा है। अगर आप यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराइए। आज तो यह हालत है कि किसी थानेदार या कांस्टेबिल के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ती है तो वह बिना डी० एम० की पर्मीशन के नहीं हो सकता है। आप पंजाब पुलिस रूल्स में अमेंडमेंट कीजिए और जैसा बाम्बे और दूसरे बड़े शहरों में है वैसा ही यहाँ पर करिए। इंटेलिजेंस का एक विंग अलग करिए। क्राइम ब्रांच है लेकिन वह इंटेलिजेंस का काम नहीं करती। क्राइम के ऊपर इंटेलिजेंस करिए। अभी तो यह पोलिटिकल पार्टीज के ऊपर ही करती है ...(**व्यवधान**)...

आखीर में एक बात कहकर समाप्त करूँगा कि मैं मानता हूँ कि अकेले पुलिस का यह काम नहीं है। जब तक उनके साथ पब्लिक का कोआपरेशन नहीं होगा तबतक काम होने वाला नहीं है। पब्लिक का कोआपरेशन लेने के लिए भी पुलिस को कोशिश करनी चाहिए। जो सोशल और दूसरे आर्गिनाइजेशन्स हैं उनका भी

[श्री कंवर लाल गुप्त]

फर्ज है कि ये जो क्राइम्स होते हैं उनके खिलाफ लोगों में जागृति पैदा करें। और पुलिस और जनता मिलकर के सरकार से पूरा सहयोग करे, इस प्रकार से अगर काम होगा तो मैं समझता हूं कि उसपर कुछ कंट्रोल हो सकता है। नहीं तो हालत यह हो रही है कि दिल्ली एक शिकागो बनती जा रही है और दिल्ली के लोगों पर एक आतंक छाया हुआ है, और कोई नहीं कह सकता कि सिक्योरिटी कहां तक है।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह समय दें और जो पुलिस कमीशन की रिपोर्ट है उस पर जल्दी से जल्दी अमल करायें।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : Delhi has crime galore with about 13,488 policemen, 75 DSPs and a galaxy of many other officers with various imported gadgets. Of course, today they are all busy for Nixon. If there is a murder, 5 murders or even 20 murders all over Delhi, you will not find a single policeman to deal with that situation. They are all there to serve the old, big Master from across the seas.

We in Delhi have been spending Rs. 3.42 crores a year for 36 lakhs citizens. That works out to Rs. 9.52 per head per annum. At the same time, people are paying Rs. 20 per head per annum for so-called defence of the country. In this wonderful city, policing is wholly in the hands of the Jan Sangh Delhid Aministration.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Not at all.

SHRI JYOTIRMOY BASU : It is in the hands of the Home Ministry. Things are happening under the very nose of that Ministry. The Jan Saugh runs the Delhi administration. Here they are collaborating and watching while they criticise when such things are happening in others States. May I tell the Home Ministry and the Jan Sangh party here : Doctor, treat thyself.

Shri Jha had said that the politicians are hand in glove with the criminals. Of course, he has modified that statement later. But we are not interested in that. It is a fact. It is a good thing that it has been said. People here have known it all along.

The Home Ministry and the Jan Sangh in order to cover up these things try to find fault with others. They whip up the press. They talk about the Rabindra Sarovar incident which is nothing but a myth. In Delhi, there have been 4 murders in a day. Nobody feels secure.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Raiganj) : He is going through a mid-summer night's dream.

SHRI JYOTIRMOY BASU : From diplomats to girl students, none is safe. An Arab diplomat was butchered the other day. A woman administrative officer of the Brazilian embassy was murdered. There was an article in *The Statesmen* graphically describing how girls students going to schools and colleges are molested, insulted and humiliated under the very nose of the Home Ministry, though they pose themselves with such efficiency as the big watchdogs.

Minorities in the city have many things to say. They have been feeling very insecure.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA : Have you studied the law and order situation in West Bengal ?

SHRI JYOTIRMOY BASU : Thefts and burglary have touched an all time high in Delhi. According to official figures, more than 5,000 thefts and burglary cases were reported during the past six months. Property worth nearly Rs. 50,000 was stolen. Kidnapping of girls also on the increase in Delhi. During January-June this year, 158 girls were kidnapped as against 128 during the corresponding period last year. Murders and attempts to kill have also registered a sharp increase during the past few months. According to official figures, 47 murders and 55 attempts to murder were reported in Delhi during the past six months as against 43 murders and 38 attempts during the same period last year. Car thefts and illicit distillation and everything else including smuggling, racketing in foreign exchange, espionage for foreign countries and all sorts of crimes are being com-

mitted. Why ? Because the British tailored police department cannot cater to people's needs. But it know how to suppress the people. They serve the purpose of their masters. Mr. Khosla said in one of his reports :

> "Among the higher staff there is lack of Proper supervision control and discipline. This must be added to the other distressing factors."

The police misuse the power and harass innocents. When we were in Tihar Jail we were told by half a dozen persons that as soon as they came out of jail they were arrested and put back. I met a man who had been in jail twenty times in the last three years. Immediately he comes out and is in New Delhi he is caught and sent back. Their past record speaks of the Sadhu riots and the events in Connaught circus on New Year's Eve. And then this 144. When trade union people demonstrate for their living, they are repressed. The whole city is an ocean of 144. We know what atrocities they committed in the Indraprastha Estate.

When it comes to a question of tackling crime, it seems they do not move because they are hand in glove with the criminals. Mr. Khosla says that except in maintaining order during demonstrations which can be done by any trained armed force, the Delhi police have been unable to acquit themselves creditably in any aspect of real police work. They are experts in suppressing people. When we led a peaceful demonstration of unemployed boys who came all the way from Kerala, we were lodged in Tihar jail for ten days. The Minister should take note that the police force is not meant to serve the V. I. Ps and isolated Government leaders who require police protection but it must serve the people. It must not all the time devote its energy to serve the V. I. Ps or do political blackmailing and tapping of our telephones or opening of our letters. Crime is generated out of Government's wrong policies and economic measures. I say orient the police to serve the people and draw the police force on a lien basis from different States. That will perhaps solve your problem permanently. They must also stop dragging them into politics.

श्री शशि भूषण (खारगोन) : सभापति महोदय, दिल्ली की आबादी बहुत अधिक है, इसकी वजह से यहां की पुलिस पूरा इन्तजाम नहीं कर पाती। उनकी संख्या और बढ़ाई जानी चाहिये। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि यहाँ पुलिस कमिश्नर बहुत जल्दी बनाया जाना चाहिये। खास तौर से चूंकि दिल्ली में खर्च बहुत ज्यादा है इसलिये यहाँ की पुलिस के जो सिपाही हैं उनके भत्ते और तनख्वाह और बढ़नी चाहिये। साथ ही जो उनकी ड्रेस है वह कम से कम और अच्छी बननी चाहिये। सारे संसार से, चाहे रूस हो, चाहे अमेरीका हो, चाहे जापान या ब्रिटेन हो, अफसरों और सिपाहियों की वर्दियाँ एक होती हैं। सिर्फ उन के स्टार्स थोड़े से बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ के सिपाहियों की वर्दिया इतनी गन्दी हैं जिसका ठिकाना नहीं है। उनको दूर दूर जगहों से आना पड़ता है, लेकिन उनके लिये बसों का इन्तजाम नहीं है। न ही उन के रहने की कोई ठीक व्यवस्था है। उनकी कोई कल्चरल बैकग्राउंड नहीं है। इन हालत में वह कैसे काम कर सकते हैं ?

दूसरी बात यह है कि यहां के थानों में ज्यादा से ज्यादा पोलिटिकल लोग बैठने लगे हैं। इस बात पर एक कमिशन मुकर्रर होना चाहिये कि कितने एम पीज जरा जरा से कामों में सिफारिश के लिये बैठे रहते हैं। मेट्रोपोलिटिन कौंसिल के मेम्बर भी आम तौर पर थानों में बैठे रहते हैं। जब भी हम वहां जाते हैं तब थानेदार और पुलिस वाले शिकायत करते हैं।

यहां जो गरीब मुसलमान और हरिजन झुग्गी झोपड़ियों में एक लाख की तादाद में रहते थे उनको यहां से बीस बीस, बाइस बाइस मील दूर भेज दिया गया है। वहां उनकी रोजी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये आज उन में से बहुत से लोग क्राइम्स करने लगे हैं। इस में कोई सन्देह नहीं है कि यहां पर पिछले दो सालों में क्राइम्स बढ़े हैं। जो यहां का लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन है अगर उसने इधर ध्यान दिया होता कि जिन लोगों को वह बाहर भेज रहा

[श्री शशि भूषण]

है वह सुविधापूर्वक वहां रह सकें तो वह इस तरह की क्राइम्स की ओर न बढ़ते। यहां के सरकारी पार्क्स में देखिये, जो अदालते हैं वहाँ के पार्क्स में जाकर देखिये, छोटे छोटे बच्चों को छुरा मारना सिखलाया जाता है, लाठी चलाना सिखलाया जाता। आखिर इस तरह से वह बड़े होकर क्या करेंगे अगर ऐटमिक एज में बच्चों को छुरा चलाना सिखलाया जाय या लाठी चलाना सिखलाया जाये ? जहां बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिये वहां यह सब कुछ होता है। इसके लिये जिम्मेदार दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन है और उस में सुधार की आवश्यकता है।

साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा कोआपरेट करे यहां के लोगों के साथ तो यहाँ की जनता जो चाहती है कि वालैंटरीली मदद द्वारा क्राइम कम हो, जन सहयोग से वह कम हो जायेगा, बल्कि बिल्कुल खत्म हो जायेगा। लेकिन कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और दूसरे जितने सरकारी डिपार्टमेंट दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन के हैं उनमें रिश्वत बढ़ी है, उनमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वह रोका नहीं जा सकता, इसलिए कि राजनीति का बहुत ज्यादा दखल हो गया है। अगर उससे थोड़ी आजादी मिले, लोकल पुलिस को थोड़ी सी सांस मिले, उनकी आर्थिक अवस्था ठीक की जाय और खास तौर से सिपाहियों को मनोबल बढ़ाया जाये तो यह क्राइम कम हो जायेंगे।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, दिल्ली में लाकानूनी बढ़ रही है, इसके बारे में कोई दो मत नहीं होंगे। मंत्री महोदय कुछ फिगर्स बतला देंगे और कहेंगे कि क्राइम बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज इस तरह के क्राइम्स बढ़ रहे हैं जो पब्लिक में होते हैं सार्वजनिक सभाओं में होते हैं। अपहरण के क्राइम बढ़ रहे हैं, जिनका आम जनता पर आतंक अधिक होता है और जिनसे लगता है कि क्रिमिनल्स का किसी को डर नहीं है। इस तरह के जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं दिल्ली में वह बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके कारण क्या हैं यह कुछ खोखला कमिशन ने बतलाया है, कुछ श्री कंवरलाल गुप्त ने बतलाया है। मैं उनमें अधिक नहीं जाना चाहता। जो दो मुख्य कारण हैं मैं केवल उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

एक कारण तो यह है कि दिल्ली में दो-अमली हैं। दिल्ली में ला-ऐंड आर्डर होम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत है और दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन का इसमें किसी प्रकार का हाथ नहीं है। यह डायर की हिन्दुस्तान में 1919 में अंग्रेजों ने प्रान्तों में शुरू की। उसका परिणाम हमारे सामने आया है। आज वही परिणाम दिल्ली में हमारे सामने आ रहा है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनका पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई चेक नहीं, और न उनकी कोई परवाह करता है। जिनके हाथ में पुलिस का कंट्रोल है उनका दिल्ली की जनता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इतना ही नहीं जो केन्द्रीय मंत्री हैं, उनमें से हर कोई चाहता है कि दिल्ली में उसकी एम्पायर बनी रहे। इस तरह के भी आम चार्जेज हैं कि उनका सम्बन्ध ऐसे बहुत से लोगों से है जो ऐन्टी-सोशल हैं। मुझे याद है 1966 में दिल्ली प्रशासन की जो पब्लिक रिलेशन्स कमेटी थी उसमें दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रधान, मीर मुश्ताक अहमद ने कहा था कि जिस समय हमारी आज की प्रधान मंत्री कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर चुनी गई, उस समय जिस व्यक्ति के साथ वह खुली कार में गई वह दिल्ली का एक मशहूर गुन्डा है, और उस समय अमृत बाजार पत्रिका और स्टैन्डर्ड में उनके चित्र भी छपे थे। जब इस तरह के देश के उच्चतम मंत्री का सम्बन्ध इस प्रकार के व्यक्ति के साथ होता तो बेचारी पुलिस क्या कंट्रोल कर सकती है। मैं यहां पर खुद किसी व्यक्ति पर लांछन नहीं लगाना चाहता, मगर मीर मुश्ताक अहमद खुद, जो

कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, दिल्ली प्रशासन की नोटिस में यह चीज लाये थे। जब तक यह चीज चेक नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी करते रहें, दिल्ली में ला-ऐन्ड आर्डर ठीक नहीं हो सकता।

इसलिए मेरा सुझाव है कि दिल्ली के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह उचित भी है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। आज तक दिल्ली का ला-ऐन्ड आर्डर बराबर केन्द्र के हाथ में रहा। लेकिन यह अनुभव फेल हुवा मेरा सुझाव है कि दिल्ली का ला-ऐन्ड आर्डर ट्रांसफर करना चाहिए दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। मगर मंत्री जी चाहते हैं कि चूँकि यहां पर एम्बैसीज हैं, और दूसरी चीजें हैं इसलिए वह अधिकार अपने हाथ में रक्खें। मैं कहना चाहता हूँ कि नई दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी का जो इलाका है, जहां पर एम्बैसीज वगैरह हैं वहां पर वह अपना एस० पी० रख सकते हैं, कुछ और अपना अधिकार रख सकते हैं, लेकिन बाकी भाग, जिसकी आबादी 40-50 लाल है और जम्मू और काश्मीर की आबादी से या हिमाचल प्रदेश की आबादी से ज्यादा है, का ला ऐन्ड आर्डर दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करना चाहिए, ताकि जो आम जनता के नुमाइन्दे हैं, जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं वह उसके बारे में कुछ कर पायें। अन्यथा यह दो अमली चलती रहेगी और यहाँ की लाकानूनी बढ़ती रहेगी।

SHRI N. SHIVAPPA (Hassan) : Mr. Chairman Sir, Delhi is the centre of the Ram Rajya of our friends. It is supposed to be the place from where we have to spread our policies. What is the position of Delhi ? It has been already pictured by my hon. friends who run the Delhi Administration now.

Sir, too many cooks spoil the broth. This is a famous proverb. There is the usual quarrel between the Jan Sangh Administration and the Central Government to have the police control in this capital city of our country. Because of this quarrel the citizens of this city, who constitute the third party, are suffering.

I think the hon. Minister has received many complaints in this regard. I want to invite his particular attention to this fact that in a South Indian colony near Moti Bagh there is a regular illicit liquor manufacturing centre which is now governed under the sanctity of prohibition, a policy for which Mahatma Gandhi sacrificed his life and left a slogan on his friends. It is continuously being run with the co-operation and in collusion with the so-called police officers in the capital city of Delhi. The residents there have said that this should be stopped as otherwise there may be innumerable murders. The hon. Minister received such a complaint and the next morning there was a murder of a teen-aged boy. Till this day not even an iota of effort has been made by the Delhi Police to investigate it and see that relief the given to the people there. Why should there be this police if they cannot protect the people ? Are they meant only to safeguard the ministers and carry their articles.

I would like to bring a very recent incident to the notice of the hon. Minister. In 'I' Block in Sarojini Nagar the wife of one of the employees of Lok Sabha Secretariat was sitting just in front of her quarter. An attempt was made by someone who came in a car to remove her necklace. This kind of daylight robbery is allowed under the misrule or inefficient rule of the Delhi Police, whoever may be the person concerned. The law and order situation in the capital is very bad. Because of this quarrel between the two administrative organs the people are feeling a sense of insecurity. Law and order in the capital has been completely paralysed.

These are the instances. We may quote innumerable cases but I want to suggest only a few points. My hon. friend has made the point that they are not properly clothed and equipped. They have been sufficiently provided with. Many quarters have been provided to them. Many buildings have been constructed. Police officers are getting a lot of bribery and they are well off economically.

My first suggestion in that there should be a uniform system of registering cases, of taking cognisance of them and then saying whether there is a cognisable case or whether there is material for the case or other-

[Shri N. Shivappa]

wise. The police officers do not at all care to take cognisance of it when a public man goes to lodge a complaint. So, the Minister should instruct the police officials to take cognisance of cases and then to gather evidence or material and seek the co-operation of the public. How can public co-operation come if police officers do not care to register cases even ?

Then, the highest man in Delhi Police administration is going to be a Delhi man and Delhi Police officials will not be transferred to other places. This gives them the determination that whatever wrong they may commit they will be happy in the capital city with all their luxury and bribery earnings. They should be changed and transferred from this place to other places. Any intelligent man in this country should be appointed to the highest post of authority in the Delhi Police administration irrespective of whether he comes from here or somewhere outside Delhi. Are they here only to construct bungalows ? There was an incident when one Mehta was the IG Police here. He had given instructions that nobody should enter his premises. If there is a good man in Madras or Bengalore, let him be put as IG of this place. Why should there be this parochial and disintegrating attitude that only Delhi people should enjoy the privilege that no police officer from here would go to other places ? This order should be changed.

Police administration is a State subject. Why is the Centre keeping it with itself ? The Central Government has got the military and other capacities to protect embassies and so many other dignitaries and VIPs. So far as the common man's administration is concerned, it is a State subject. The Government must decide and see that the police administration is handed over to the State administration. When the Jana Sangh says this, it may be parochial, but when we people also say that, it must be taken into consideration. I hope, the hon. Minister will concede this.

It is a very important subject and there are many suggestions that I want to make. Please give me two minutes just to make suggestions.

MR. CHAIRMAN : Please finish your speech now. There are many speakers from different parties.

SHRI N. SHIVAPPA : So far as lodging of complaints is concerned I want that education for lodging complaints should be started by the police. If I take a complaint to the police station, I will write it in my own language and I do not know law. So, there should be an education campaign by the Police Department to educate people on how to lodge complaints in a particular language, whether Hindi or English. If a police officer receives a complaint, he says that it is a bogus complaint and throws it in the waste paper basket. So, let there be education for the poor and the innocent people who do not know how to lodge a complaint. The question of investigation requires the technique of a police official, so to seek co-operation from the public let there be a system of education.

I have so many other suggestions to make which are very valuable, But in the interest of the public and the nation, it is high time that the Minister put his concrete inclination to see that some change is brought about both in the administration and other thing and clear out the abhorrence in the mind of the public and at least get a good name in the interest of the nation though not in the interest of his party.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ज्यादा समय न लें । बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । अगर माननीय सदस्य थोड़ा-थोड़ा समय लें, तो काफी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सकता है ।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : चेयर मैन साहब, टाइम बढ़ाना पड़ेगा ।

सभापति महोदय : टाइम को नहीं बढ़ाया जा सकता है ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैंने चिट्ठी लिखकर दी हुई है । क्या मुझे बुलाया जायेगा या नहीं ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अभी अपनी सीट पर नहीं थे । इसलिये मैंने श्री

बाजपेयी को बुला लिया। अब उन्हें बाद में मौका दिया जायेगा।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : दो मिनट मुझे भी दिये जायें।

श्री कंवरलाल गुप्त : थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाये।

श्री इसहाक सम्भली : चेयरमैन साहब, थोड़ा टाइम तो बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री कुण्डू।

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati): Unless you extend time, how can you accommodate them ?

MR. CHAIRMAN : I will adjust that but I am not going to extend the time.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Mr. Chairman, Sir, we have discussed this matter many times in this House. Whenever we want certain things to be done on the basis of the khosla reports submitted, the Government has come out with a positive a positive denial. The question is in what attittude you are going to see the police administration. That is the moot point here.

The British people used police as an implement of coercion. The British people equipped police only with *danda*. When they thought of having a *daddaraj*, they utilised the police. With the change of times, we have never given new orientation, a new outlook, to the police administration. The British people kept the police at the lowest income level because they did not bother about its utility to Seciety. They somehow through training inculcated all animal instincts. Whenever they wanted them to open fire and use *lathis*, the police force was trained to oblige them.

In the last twenty years, the police force have not basically changed. Before we go into all the problems, we would like to analyse the type of crimes. Particularly, in big cities like Delhi, there are different types of crimes. One type of crimes is a psychological phenomenon, the crimes committed by the affluent section of the society and the sons of the affluent fathers and mothers. They pick up such hobbies which make them indulge in a spree of vulgarisation. Then, there is another type of crimes performed by the habitual offenders, foreign exchange racketeers and such other offenders. There are other type of crimes which take place behind the screen in the darkness of the night. To study these things, to understand these problems and to meet these challenges, some sort, of basic capacity is necessary. Training is necessary. Lot of education is necessary ; a better quality police force is necessary. The Khosla Commission has said that. Can you ever think of semi-illiterate constable getting Rs. 70 to understand all these things ? It is impossible : You want to entrust law and order problem in city like Delhi to a constable who gets Rs. 70 or so ? The Khosla Commission has said that Rs. 125 should be minimum wage for constables. The minimum wage of workers in factories in Delhi is Rs. 230. The Government is not prepared to accept the recommendation. Unless you go into basic things, you cannot achieve anything.

There are two aspects of the Khosla Commission Report. One aspect deals with the emoluments of the police. Another aspect is how the deficiency in the police administration could be rectified. I want a categorical answer from the hon. Minister. These things could be sorted out in two days. Give me police administration and in two days I will set it all right. You sit with the police officers and others and see whether you can square out the deficiency which has been pointed here. Khosla Commission says there is no structural integration. Nobody knows who is the master in the police administration. You can set it right in one day. You can make the Commissioner or somebady responsible for the entire department. Nobody knows who is to obey whose command.

The Commission has said that there is no proper system for prosecution, investigation beat and patrol. You can set right things in one day. They have also said that there is frustration in the mind of the police. I will read out these lines. This is basically

[Shri N. Kundu]

a psychological matter. The Khosla Commission says :

> "The policeman feels frustracted and disturbed when he finds that he cannot afford to see any cultural show, cannot buy luxury goods, cannot pay for a good meal though the hotels serve delicious dishes. This works on his mind and demoralises him. He cannot afford to enjoy many of the pleasures which the City of Delhi provides for its inhabitants."

I do not say that you should give him all these luxuries. But you should at least train him to meet the challenges coming from an affluent society. The policemen in the rural side have to work even without shoes. The Khosla Commission says that you have not provided him with special training to have the orientation to meet these new challenges. Why don't you provide this ?

Hundreds of policemen are being harassed because of the past strike. They are dragged to Court as prosecutions goes on. I would ask the hon. Minister to be a little more generous to them and not be petty. They have been sufficiently harassed. This itself has been a type of punishment. I would request the Minister to take back, withdrawume those cases. He may also please implement the emoltants recommended by the Khosla Commission. He may also settle the other deficiencies, which have been pointed out here and can report in two days that he has done it.

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : सभापति महोदय, दिल्ली में जुर्म बढ़ने के कारणों पर सोचते समय मैं मंत्री जी से कहूँगा कि वह यह जरूर सोचें कि दिल्ली दो हैं—एक नई दिल्ली है और एक पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली में रिक्शे चलते हैं, जामा मस्जिद के पास 20 पैसे देकर आदमी चारपाई पाता है और सो लेता है, ऐसे ही सड़क पर और फुट पाथ पर भी सोता है और इधर नई दिल्ली में फव्वारे बनते हैं। तो जहाँ इंसान की जिन्दगी, रहनसहन और खानपान में इतना बड़ा फर्क होगा वहाँ जुर्म और कत्ल होंगे ही। ऐसे तो नई दिल्ली में भी कत्ल होते हैं लेकिन वह रक्तहीन कत्ल होते हैं जैसे मोरार जी भाई का कत्ल हो गया, सांस चलती रही, काम रुक गया, नाम हट गया। मेनन साहब का भी कभी कत्ल हो गया था। इधर दौलत के लिए और गद्दी के लिए क़त्ल होते हैं और उधर छोटी-छोटी बातों पर, मामूली चीज पर, जेबकटी के सवाल पर झगड़े हो जाया करते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर दिल्ली से जुर्म और कत्ल हटाना है तो यह बात वह अपने दिमाग में रखें कि सारी दिल्ली को नई और पुरानी के नाम से न पुकार कर एक दिल्ली बनाएं। ऐसे ही इन्होंने हिन्दुस्तान को भी बांटा है। कहीं हजरतगंज के नाम पर, कहीं सिविल लाइन के नाम पर, कहीं माल रोड के नाम पर, कहीं चौपाटी और चौरंगी के नाम पर सारे हिन्दुस्तान के शहरों के दो हिस्सों में बांटा है। इंसान की जिन्दगी में फर्क आया है और जिन्दगी में फर्क आने के साथ-साथ इंसान की जिन्दगी की कीमत में भी फर्क आपने किया है। आज दिल्ली में आप देखिए निक्सन साहब आए हैं। जगह-जगह बल्लियां गड़ी है। मंत्री लोग हमारे चलते हैं, पुलिस वाला खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ साधारण आदमी सड़क पर चलता है और कोई पीछे से छुरा मार देता है, वह दम तोड देता है। तो यह जो जुर्म बढ़ते हैं इसमें एक तिगड्डा काम करता है, त्रिकोण होता है गुण्डों का, प्रशासन का और अमीरों का। यह तीनों मिले जुले रहते हैं। यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि राजनैतिक लोग भी इसमें हिस्सा लिया करते हैं या गुन्डों को प्रश्रय दिया करते हैं। मैं झां साहब के बारे में ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं। यह हमारे इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक दिन मैं इनके घर के मुहल्ले से आ रहा था। मैं नहीं जानता था कि यह कहां रहते हैं। जार्ज टाउन में वैसे यह रहते हैं। उधर मैं रिक्शे से चला आ रहा था तो वहां पर देखा कि पुलिस के सिपाही खाकी वर्दी में एक मकान की चहारदीवारी बना रहे थे। मैंने एक लड़के

से पूछा कि यह किसका घर है तो उसने बताया कि दिल्ली के किसी मालिक का घर है। श्रीमती इन्दिरा गांधी का भी घर इलाहाबाद में है। मैं जानता हूँ कि उनके घर में पुलिस का सिपाही नहीं रहता। जब वह जाती हैं तो रहता है। लेकिन जो आदमी अपने ओहदे का इस्तेमाल करता है अपने घर की चहारदीवारी बनाने के लिए, उसमें पुलिस के सिपाही से काम लेता है तो उसकी पुलिस का सिपाही जनता से घूस लेगा ही, इसमें कोई बहस की बात नहीं है क्योंकि खिसकाव तो ऊपर से ही होता है। ऐसी हालत में मैं आप से प्रार्थना करूंगा केवल दो तीन बातों के लिए। (1) आप इस बात के लिए यहां गृह मंत्री साहब से कहिए, मैं शुक्ला जी से खास तौर से कहूँगा क्योंकि जो मैंने रक्तहीन हत्या की बात कही थी, मुझे डर है कि पन्द्रह बीस दिन के बाद इनके बड़े मंत्री जी चव्हाण साहब की भी हत्या होगी···

सभापति महोदय : इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है···(**व्यवधान**)···

श्री जनेश्वर मिश्र : इसलिए मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि यह खास तौर से दोनों दिल्ली को एक करें और इसके साथ-साथ कुछ अफसरों के लिए एक संहिता बनाए कि अगर पांच हत्याएं होती हैं या एक बार दंगा होता है तो जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा चाहे वह पुलिस कप्तान हो या जिलाधीश हो, उसके कैरेक्टर रोल में वैड एन्ट्री बिना कुछ सोचे ही दे दी जायगी क्योंकि आखिर कलेक्टर और कप्तान होते किस लिए हैं। जुर्म रोकने के लिए ही तो होते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। दिल्ली में हर साल प्रशासन में हम देखते हैं कि जुर्म बढ़ते हैं और जुर्म बढ़ने के बाद यहा का लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता है। कई बार यह भी हुआ है। इसलिए एक संहिता द्वारा कहीं न कहीं यह रोक अफसरों के लिए लगाइए।

दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा मंत्रियों से कि पुलिस का विकेन्द्रीकरण करें। जो जिला परिषदें हों या कारपोरेशन हों शहरों के अन्दर उनके हाथ में आर्म्ड पुलिस को तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन साधारण पुलिस दे देनी चाहिए ताकी मुकामी तौर पर उसका इस्तेमाल जो मुकामी तौर पर वोट लेकर आते हैं वह लोग कर सकें। इसके साथ-साथ मैं इनसे कहूँगा, मैंने अभी एक चिट्ठी लिखी थी – केवल दिल्ली की बात नहीं है, सारे हिन्दुस्तान की बात है, उसमें मैंने बताया कि एक चार साल का बच्चा कत्ल कर दिया गया एक देवी के मन्दिर में। उसमें मैंने उनको लिखा कि एक थाने के अन्दर पुलिस ने एक आदमी को ले जाकर कत्ल कर दिया। फिर मैंने लिखा कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं अभी आप अखबारों में पढ़े होंगे...**

सभापति महोदय : यह बात रेकार्ड पर नहीं जायगी।···(**व्यवधान**)···यह प्रान्त की चीज है, यह चीज रेकर्ड में नहीं जायगी।

श्री रवि राय (पुरी): यह अखबार में आया है।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं किसी प्रान्त का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं जनरल बता रहा हूँ···

सभापति महोदय : आप दिल्ली की बात कह रहे हैं, दिल्ली की बात कीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : इन सवालों पर मंत्री जी कह देंगे कि यह प्रान्त का विषय है लेकिन जहां तक इन्सान की जिन्दगी का और कत्ल का सवाल है, मैं यही सिफारिश करूंगा मंत्री जी से और आप से भी कहूंगा, इस सदन से भी कहूंगा कि इंसान की जिन्दगी जहां जा रही हो वहां वह किसी सूबे का, किसी जिले का विषय नहीं होना चाहिए, वह केन्द्र का विषय होना चाहिए।

** Not recorded.

[श्री जनेश्वर मिश्र]

इसके साथ-साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि यह नई और पुरानी इन दो व्यवस्थाओं को एक साथ बदलने की बात करेंगे तो यह कहीं जाकर दिल्ली का जुर्म खत्म कर सकेंगे ।

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : I came to Delhi in 1950 as security prisoner. Again I came here in 1954 for my party meeting—then I was staying in South Avenue. Then I did not come across any news in papers about murders and theft like these years. Now when I have come here in 1967—as M. P., daily I am reading news about murders, burglary, thefts, kidnapping going on. Shrimati Naidu, wife of an air force officer, who was missing sometime ago is still untraced. In 1967, one women from UP came here with her family and met Shrimati Indira Gandhi, the Prime Minister, complaining that her daughter had been taken away from near about Delhi and was not traced. Today I have read a report in the press that in Pusa Road a necklace was snatched away. We have read in the *Statesman* about girl students going to school or college being molested and insulted by young boys or goondas. I fail to understand all these things. The political administration here is under the Jan Sangh. Why do they not openly condemn these things ?

18 hrs.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We have done it.

SHRI DHIRESWAR KALITA : Here the Lt. Governor has come out with a statement that some influential political parties are sheltering these goondas. Who are they in Delhi ? Certainly not the Communist Party, certainly not the Congress. It is certainly the Jan Sangh.

SHRI RABI RAY : And Congress.

SHRI DHIRESWAR KALITA : Who is controlling the police ? Shukla Sahib. Law and order is not within the province of the Delhi Administration. But for their political purposes, they may be sheltering goondas. Both these parties may be doing this. So both are uniting to murder citizens of Delhi.

SHRI S. M. BANERJEE : both should be hanged.

SHRI DHIRESHWAR KALITA : Some ways and means should be found out to put an end to this situation immediately. It should be the responsibility of the ruling party in the Territory as well as that of the Government of India to do that.

Shri Kundu mentioned that in the last one year 3,000 cases of policemen are pending. More than 500 policemen have already been suspended or dismissed. Here there is a Police Karmachari Sangh. If ordinary policemen are not taken into confidence by the administration, how can one official or two inspectors or sub-inspectors go and control these criminals ?

MR. CHAIRMAN : That would do. Shri Abdul Ghani Dar.

श्री अब्दुलगनी डार (गुड़गांव) : चेयरमैन साहब, मैं अपने दोस्तों के सामने चार बातें रखना चाहता हूँ । सन् 47 की दिल्ली से सन 69 की दिल्ली बिलकुल मुखतकलिफ हो गई हैं, दुनिया भर के मोअज्जीन यहाँ आते हैं, मेहमान आते हैं, हिन्दुस्तान भर के एजिटेशन्ज यहाँ चलते हैं —यह बात आपको अपने सामने रखनी चाहिए । दूसरी बात—दिल्ली की आबादी इतनी ज्यादा हो गई है, मुखतलिफ प्रदेशों के लोग यहाँ आकर बस गये हैं, उनकी निगहबानी करना काफी मुश्किल हो गया है । तीसरी बात—एक हजार के करीब पुलिस वालों को इन्होंने इसलिए डिस्मिस कर दिया था कि उन्होंने यूनियन बना ली थी, उनको इन्होंने रिएप्वाइन्ट नहीं किया और चौथी बात—पुलिसवालों को जो इस वक्त मिल रहा है, वह हरियाणा, पंजाब से कहीं कम मिल रहा है । ये चार बातें सामने आ जायें तो कत्ल और गुन्डा-परवरी की जो बात सामने आई है उस पर गौर किया जा सकता है ।

सबसे पहली बात मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जिनके ऊपर इनको गुस्सा आया था, जिनको डिस्मिस किया था, उनको बहाल

कर दें और हरियाणा और पंजाब के मुताबिक यहाँ की पुलिस की तनखाहें कर दें, पुलिस की तादाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें, इसलिए कि इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है तब यह मसला हल हो सकता है - मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि पुलिस सेन्टर के कब्जे में न रहे । यहाँ कि पुलिस सेन्टर के कब्जे में ही रहनी चाहिए, लेकिन सेन्टर को अपनी कामयाबी दिखानी चाहिए ताकि मेरा जो ख्याल रहा है कि तमाम स्टेटों में सिर्फ एक रिजनल कमेटी या एडवाइजरी कमेटी बनाई जाय और तमाम मुल्क का ला एण्ड-आर्डर सेन्टर के हाथ में रहे- वह पूरा हो सके । मैं शरमिन्दा हूँ कि हमारी यूनियन सरकार इसमें कामयाब नहीं हुई । में इसमें किसी की बदनीयती नहीं समझता, न जनसंघ को इल्जाम देता हूँ और न कम्यूनिस्टों को देता हूँ, न कांग्रेस को देता हूँ । मैंने अपनी बदकिस्मती का रोना भी नहीं रोया है । बासू जी पकड़े गए तो यहीं रहे, लेकिन एक मुसलमान पकड़ा गया, मस्जिद के मामले में तो उसको चार महीने के लिए अम्बाला जेल में भेज दिया गया । जैसे इनकी इच्छा हो करें, मुसलमान के साथ एक सलूक करें और बासू के साथ दूसरा करें— इन की मर्जी ।

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگانوں): چیرمین صاحب میں اپنے دوستوں کے سامنے چار باتیں رکھنا چاہتا ہوں—۱۹۴۷ کی دلی سے ۱۹۶۹ کی دلی بالکل مختلف ہو گئی ہے - دنیا بھر کے عزیزین یہاں آتے ہیں - مہمان آتے ہیں - ہندوستان بھر کے ایجیٹیشنس یہاں چلتے ہیں - یہ بات آپکو اپنے سامنے رکھنی چاہئے - دوسری بات - دلی کی آبادی اتنی زیادہ ہوگئی ہے، مختلف پردیشوں کے لوگ یہاں آکر بس گئے ہیں، انکی نگہبانی کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے - تیسری بات—ایک ہزار کے قریب پولیس والوں کو انہوں نے اس لئے ڈسمس کر دیا تھا کہ انہوں نے یونین بنا لی تھی، انکو انہوں نے ری اپوائنٹ نہیں کیا -

اور چوتھی بات—پولیس والوں کو جو اس وقت مل رہا ہے وہ ہریانہ، پنجاب سے کہیں کم مل رہا ہے - یہ چار باتیں سامنے آجاتی تو قتل اور غنڈا پن وری کی جو بات سامنے آئی ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے -

سب سے پہلی بات—میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنکے اوپر انکو غصہ آیا تھا، جنکو ڈسمس کیا تھا انکو بحال کر دیں اور ہریانہ اور پنجاب کے مطابق یہاں کی پولیس کی تنخواہیں کر دیں - پولیس کی تعدا دکو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اسلئے کہ انکی ذمہداری بہت بڑھ گئی ہے - تب یہ مسلہ حل ہو سکتا ہے - میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ پولیس سینٹر کے قبضہ میں نہ رہے - یہاں کی پولیس سینٹر کے قبضے میں ہی رہنی چاہئے - لیکن سینٹر کو اپنی کامیابی دکھانی چاہئے تاکہ میرا جو خیال رہا ہے کہ تمام اسٹیٹوں میں صرف ایک ریجنل کمیٹی یا اڈوائزری کمیٹی بنالی جاۓ اور تمام ملک کا لا اینڈ آرڈر سینٹر کے ہاتھ میں رہے - وہ پورا ہو سکے - میں شرمندہ ہوں کہ ہماری یونین سرکار اسمیں کامیاب نہیں ہوئی - میں اسمیں کسی کی بدنیتی نہیں سمجھتا، نہ جن سنگھ کو الزام دیتا ہوں اور نہ کمیونسٹوں کو دیتا ہوں اور نہ کانگریس کو دیتا ہوں - میں نے اپنی بدقسمتی کا رونا بھی نہیں رویا ہے - باسو جی پکڑے گئے تو یہیں رہے، لیکن ایک مسلمان پکڑا گیا مسجد کے معاملے میں تو اسکو چار مہینے کے لئے امبالہ جیل میں بھیج دیا گیا - جیسے انکی اچھا ہو کریں - مسلمان کے ساتھ ایک سلوک کریں اور باقیوں کے ساتھ دوسرا کریں، اُنکی مرضی -]

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, एक बात तो मैं इस वास्ते कहना चाहता हूँ कि यहां पुलिस के जितने आदमी हैं, उनमें से 95 फीसदी हरियाणा के हैं । मैं कई

[श्री रणधीर सिंह]

दफा कह चुका हूं—चव्हाण साहब से भी और मिनिस्टर साहब से भी वह जो तलवार लटक रही है उनकी गरदन पर, आखिर उसकी हद होती है। उन्होंने गलती की थी उनका सिर्फ इतना कुसूर था कि उन्होंने जलूस निकाला था, लेकिन तीन साल से उनके मुकदमें लटक रहें हैं। सभापति जी, आप जानते हैं, आप भी एक बहुत पुराने इन्कलाबी रहे हैं तीन साल तक किसी गरीब आदमी को मुकदमें में फंसाये रखना अदालत में जाना, पुलिस की हाजिरी देना कितनी दिक्कत की बात है। मैं चाहता हूं कि उनके साथ अब कुछ हमदर्दाना सुलूक करें। अगर उन आदमियों को पुलिस में नहीं रखना है तो अपनी जिम्मेदारी पर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एम्पनाय कर दें। इसको डिस्प्लिन और प्रेस्टिज का सवाल न बनाये। मैं हाथ जोड़कर गवर्नमेंट से इल्तजा से करना चाहता हूं—3 हजार आदमी हैं, उनके साथ कई हजार का कुन्बा है।

दूसरी बात—हरियाणा के आदमियों को जब पुलिस में भरती नहीं किया जा रहा है। जितने पहले किए जाते थे, उससे बहुत कम किया जा रहा है। यह मेरी शिकायत है। जय जवान और जय किसान वाले लोग, जिनकी बहादुरी से चीन और पाकिस्तान भी खौफ खाते हैं, उनके सपूतों को, रिश्तेदारों को पुलिस में भरती न करना एक डिस्क्रीमिनेशन है। तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि यहां पर दिल्ली में जो सेटअप है वह बड़ा अजीब है—कारपोरेशन कमेटी, डी० डी० ए० और सेंट्रल गवर्नमेंट—यह मेरी समझ में नहीं आता कि है क्या ? यह चूं चूं का मुरब्बा है। इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। आखिर यह कंफ्यूजन क्यों है ? इस मुल्क में और भी सेन्ट्रल टेरिटरीज हैं, आखिर वही चीज दिल्ली के साथ भी क्यों नहीं है। फिर दिल्ली के साथ देहात भी हैं, दो तीन बड़ी बड़ी तहसीलें भी हैं, आखिर उनका कारपोरेशन से क्या सम्बन्ध हो सकता है। इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। आप दिल्ली के लिए आराम से बैठ कर किसी सेटअप की तजवीज करें जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड देने जा रहे हैं—बी या सी क्लास जो भी बनाने वाले हैं उसमें पूरी पावर्स दीजिए आप इनके ऊपर इन बातों को भी छोड़िए, आपने अपने ऊपर की सारी जिम्मेदारी क्यों ले रखी है। ये लोग तो कुछ करते नहीं हैं। तबेले की बला बंदर के सिर डालिए। वैसे यहाँ पर क्राइम का इंसिडेंस कम है। लेकिन आप सब कुछ इनके ऊपर ही डालिए। अगर ये नहीं करेंगे तो पब्लिक इनको उठाकर फेंक देगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि दिल्ली के लिए भी फुल स्टेटहुड हो। जैसे कि आपने त्रिपुरा, मनीपुर, गोवा में कर रक्खा है उसी तरह से यहां पर भी कीजिए। मैं समझता हूं मन्त्री जी मेरी तजवीज पर गौर करेंगे।

श्री राम गोपाल शालवाले (चांदनी चौक) : मैं केवल एक बात मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कटरा नील में रानी टंडन की जो मौत हुई, 8 जून को शादी हुई और 14 जून को लाश उसके बाप के सुपुर्द कर दी गई, मैंने इस में मन्त्री जी को दो पत्र लिखे हैं, अखबारों की बारे कटिंग भी भेजी है, उपराज्यपाल महोदय को भी लिखकर दिया, उनकी चिट्ठी मेरे पास है कि सी० बी० आई० को केस देने में उन्हें कोई एतराज नहीं है तो क्या मन्त्री जी का विचार इस केस को सी० बी० आई० के सुपुर्द करने का है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं रणधीर सिंह जी का समर्थन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के जितने भी कर्मचारी सस्पेन्डेड या डिस्चार्ज्ड हैं, उनको काफी अरसा हो गया है, उनको फौरन वापिस लिया जाये ताकि ला एण्ड आर्डर को ठीक करने में काफी मदद मिल सके। वे इस देश के सच्चे सिपाही हैं—जो अपने डिमांड के लिए लड़ सकते हैं वे देश के लिए भी लड़ सकते हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Mr. Chairman, Sir, the Delhi Police does not have a very long history of its own, and as hon. Members know, Delhi grew from a small city of 3½ lakh people, in 22 years, to a sprawling city of 36 lakhs of people. The population of Delhi is increasing day by day. If you compare the incidence of crime in Delhi per lakh of population it can be easily proved that the incidence of crime in Delhi is much less than in many other big cities of the country, (*Interruption*).

SHRI KANWAR LAL GUPTA : No.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have got the official figures, but I do agree with Shri Kanwar lall Gupta. I do not want to quote statistics, because that is not the way of conveying our idea or even convincing the people. The people must be convinced by the action or by the very results that the Delhi Police shows. I do not want to convince people by statistics, but I am merely mentioning that it is not a question of Delhi Police being inefficient or Delhi Police being a particularly corrupt police force. But this is a peculiar condition, a queer condition of Delhi, which has brought about this kind of situation here.

Now, Sir, if we analyse the problems we can see many things. First of all, there is the composition of the force. It has no cadre of its own as most of the police forces in this country have. This police force has grown mostly by deputation, by people coming from various police cadres like those of Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab-Haryana, Madhya Pradesh and other adjoining territories. They would do their work here, whether good, bad or indifferent, and they will go back. They had no roots here and they did not belong to this cadre. They did not consider themselves as members of the Delhi police force. This was one of the complicating factors.

I am mentioning some of the difficulties which have come in the way of proper functioning of this force. I would say that there should be no wholesale condemnation of any force. There are all kinds of people. There are bad people and there are good people, there are good workers and there are bad workers, there are good officers and there are bad officers. But to say that the entire force is corrupt, is inefficient and not working properly is not correct.

AN HON. MEMBER : Most of them.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Not even most of them. We find that the misdeeds get a good deal of prominence, which is normal in human nature and human affairs, and good deeds generally do not get prominent display either in news or in publicity. Quite a lot of good things are done by the Delhi police personnel, but they would never find a place in publicity because they are expected to do that and nobody thinks these have any news value. If something wrong happens it finds a place in news. I am not saying that wrong things do not happen. What I say is that wholesale condemnation which some hon. Members have made is not proper and is not conducive to the proper working of any force. It will demoralise even the good workers in the force.

I would request hon. Members to realise the tremendous difficulties faced by the ordinary constables, the vulnerable positions in which they are placed and the difficult situations in which they are called upon to discharge their duties. If you consider the conditions under which the Delhi constables, head constables, Assistant sub-inspectors and even sub-inspectors work and are required to discharge their duties you will find that lots of people who blame these people for not doing their work properly will be more sympathetic when they know that these people have been trying to discharge their duties in a very good manner, in a conscientious manner and under very difficult circumstances when they are particularly faced with a hostile public opinion, which is a legacy of history to begin with and which is again due to the kind of atmosphere that prevails. It is no individual's fault. Even if an honest individual in the Delhi police force wants to work honestly everybody suspects him and nobody gives him any cooperation. He is therefore forced to do things which he may not like to do. I am not saying that whatever they do is right or there are no faults, but this aspect of an ordinary worker in the Delhi police force must always be taken into account when you are judging the performance of the police force here.

[Shri Vidya Charan Shukla]

For the first time, Sir, when the Khosala Commission was appointed all these difficulties of the lower staff of the Delhi police force were taken into account, analysed in a proper manner and a series of recommendations have been made. These recommendations have a large amount of financial implications and other implications also. With a great deal of effort we have scrutinised all the recommendations that they have made. We have implemented a good many of them and we are going to implement most of the remaining ones. But it is going to take a little time.

As I said earlier, before the Khosla Commission was appointed I do not think there were any systematic or scientific attempts to analyse the working conditions, the situation that the Delhi policeman faces and the peculiar conditions that are obtaining in Delhi. Nothing of this kind of thinking was done. Now it has been done. We have got an expert committee's report with us. That report has been analysed. About most of its recommendations we have taken decisions and those recommendations are under implementation. The effect of their implementation will be obvious after some time. Overnight this kind of a situation cannot be improved.

In big cities where there is a large history of police functioning, like Bombay, Calcutta, Madras, Hyderabad, Bangalore etc., if you see the statistics you will find that conditions are worse than they are in Delhi. Still, without deriving any consolation from such statistics I would say that there is a lot of room for improvement here. We have to improve not only in techniques but also in organisation, equipment etc. We have also to improve in the working as many hon. Members mentioned.

There are peculiar problems in Delhi which no other capital city faces, like the visit of international dignitaries very frequently, a large amount of international population in this city and this being the seat of power many other things come along with the seat of power. Many businessmen and all kinds of people come here for work and many things happen. This Union territory is surrounded by four or five big States. Also, all kinds of criminals come and go without any check. Delhi being a Union territory, we have seen that inter-State gangs of criminals operate here and go over to adjoining States to escape the punishment of law. Take, for example, the car or scooter thieves. If such thieves steel a car in Lucknow or Patna, they will take a little time before they can get out of the State boundary but if here some such kind of theft takes place, the thief can go out of the Union territory between 20 to 30 minutes. Then it becomes a very complicated process to nab them. I am only pointing out the difficulties that are being faced here.

About corruption I would not say that there is no corruption in the Delhi police force. Corruption does axisl but it should be our duty not to play up this kind of corruption and generalise and say that every body is corrupt. We have known instances of very honest policemen right from the constable's rank up to the higher ranks who have been working devotedly and are trying to serve the people to best of their ability. But there are others also who are spoiling the atmosphere and give the impression to us that the police force is corrupt.

To find out the real malady and what we can do about it, we entrusted a sample study to the CBI. They took three or four police stations of Delhi as a sample study, studied them for a few months and have given us a report. We are analysing that report and on the basis of that report we will take some action to improve the working and to reduce the chances of corruption.

The Khosla Commission has also given some suggestions and hon. Members also have given some useful suggestions. As a matter of fact, a good many of the suggestions that Kanwarlal ji has given are already under our consideration. We will definitely consider them and see how soon they can be impletmented.

As far as the question of transfer of officers is concerned, I have already explained that because this cadre is a completely independent cadre, particularly the subordinate police officials, we have found it difficult to transfer them to other Union territories. As a matter of fact, I do not find it a very appealing proposition to transfer one corrupt officer from here to another territory, because this is no punish-

ment, this is no remedy. As a matter of fact, if a man is corrupt here, he may go to a far-flung Union territory like Pondicherry or Goa and practise corruption there. This is, really speaking, no solution to corruption. For that, we will have to devise a system by which we can nab them and punish them so that they do not indulge in corrupt practices. If anybody indulges in corrupt practices, he should be punished properly. That is the only way of doing it...(*Interruptions*) I have no time ; I am not yielding. I am trying to cover as many points as possible. We are thinking in what way we can handle this question of subordinate police officers, whether we can make their jobs transferable and, if it can be made transferable, whether it will really help us to check their working in a proper manner or check corruption in their ranks. If we can do so, then we shall consider how we can do it.

Some hon. Members mentioned the case of discharged policemen. This matter has been discussed in the House very many times. It is not a question of taking any hard line. It is a question of maintaining discipline in the courts where discipline is of the utmost value. Therefore, we have made it clear here many times that it will not be possible to reopen that case and we can do nothing about these people who have been discharged from their duties, for their work. As far as the question of disposal of cases is concerned, the cases can be disposed of if there are no obstructions. But if people go to High Courts and other courts and get writ petitions and stay orders, then naturally the cases are prolonged.

SHRI RANDHIR SINGH : Have mercy on them....(*Interruptions*)

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : All that can be considered after the cases are over. But before the cases are over, how can we consider anything like that. They should not try to obstruct the legal proceedings...(*Interruptions*) I am sorry I am not in a position to oblige any of these people. I am not yielding.

I have already clarified that matter where the Lt. Governor was reported to have said that some politicians are harbouring goondas in this Union territory and that they get encouragement from politicians. I have already clarified the matter in the other House. Here, I will briefly say that the Lt. Governor was misquoted ; he has also indicated what he actually said that the criminals here are trying to browbeat the law and order...(*Interruptions*) And they say they have the protection of the politicians here. I am sorry Mr. Madhok mentioned the Prime Minister's name...

SHRI BAL RAJ MADHOK : I mentioned, not on my authority, on the authority of Mir Mustaq Ahmed. You enquire from that authority.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I am not aware of what Mir Sahib said. But whosoever may have said, it is a common knowledge that anybody, not only in this country but in any country, can go and see the Prime Minister and they can sometimes take photographers and have themselves photographed like that. That is not the responsibility of the Prime Minister as to who gets photographed with her. To say that somebody has got photographed with her and that is why he has got protection is a travesty of truth. It is not a proper thing to say. I want to emphatically say that this kind of a statement is not going to confuse the public and the hon. leader like Mr. Madhok should not have said that.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I did not say on my own authority.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Having said that, I would like to assure the House that we are, at present, in the process of improving the police force in Delhi As I have already said here, the functioning of the police force in Delhi is no worse than that of in Bombay or Calcutta or Madras. As a matter of fact. It is better than that. I would say, It requires a lot of improvements and we are willing to make those improvements. As I said, we are considering the question of appointing a Police Commissioner in Delhi. We hope to take a decision about it very soon. After we have taken a decision about it. I am sure that that decision will also help in streamlining the working. We want to give modern gadgets to the police force for detection of crime and for inquiry. We also want to

[Shri Vidya Charan Shukla]

give them greater mobility ; we want to give them better and more efficient systems of communications so that the functioning becomes better. We also want to give them better housing facilities so that the conditions of living and conditions of working become better. We have already done a good deal in this and we want to do a lot more in future. One hon. Member said that some dresses should be changed and the working conditions should be improved. We are all trying to do that. Within two years, I hope, the hon members will find some difference some improvement, in the working. With that intention we are effecting improvements in the Delhi police force. I am not saying that the Delhi police force is the ideal force. Still, wherever the law and order position is considered in the House, the hon. members must always take into account the historical reasons as well as the prevailing conditions. In this background if a judgement is to be made, I am sure, the performance of the Delhi police is not as bad as it has been made out here.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

18 32 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 1, 1969/ Sravana 10, 1891 (Saka).

Printed at Imperial Book Depot Press, Jama naszid, Delhi.